Writ Petition No.13471/2015

24.08.2016

Shri Sunil Pandey, learned counsel for petitioner.

Ms.Janhvi Pandit, learned Government Advocate for respondents No.1, 2 and 3.

Shri H.Upadhyay, learned counsel for respondent No.4.

With consent of learned counsel for the parties, the matter is finally heard.

Petitioner calls in question the correctness of order dated 27.05.2015 passed by Collector, Seoni in purported exercise of his powers under Section 21 and 22 of the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007, read with Rule 19 of M.P. Maintenance and Welfare of Patents and Senior Citizens Rules, 2009.

Respondent No.4, a septuagenarian invoking the provision of Section 21 of 2007 Act filed an application before the District Magistrate, Seoni seeking indulgence that having retired from the service of State Bank of India, as Branch Manager in the year 1998, he settled down in the house situated at Somwari Bajar, of his ownership. That, in the year 2013, the applicant suffered heart ailment and had to take medical treatment at Bangalore and Jabalpur. That, while undergoing a treatment at Jabalpur in 2014, the petitioner, younger son of respondent No.4, who was married

on 10.12.2013, reportedly started demolishing the house with an intention to construct a new house thereover and denied the access to respondent No.4.

On being noticed by the District Magistrate, the petitioner herein denied all the contentions and claiming the house in question to be an ancestral property having 1/6th share in the said house, justified his action. Besides, an objection as to jurisdiction of the District Magistrate under Section 21 of 2007 Act to entertain an application, which otherwise was tenable under Section 5 before the Tribunal constituted under Section 7 of 2007 Act, was also raised by the petitioner, who sought the dismissal of complaint being beyond the jurisdiction of the District Magistrate. On the application report was sought from Sub-Divisional Officer (City) Seoni. The report was furnished on 15.04.2014 whereon, the District Magistrate declined to grant any interim relief by order dated 16.04.2014. The order was challenged before the Commissioner, Jabalpur Division, Jabalpur. That, by order dated 02.09.2014 the Appeal was disposed of on 02.09.2014 with an observation that the Collector will take a decision on merit. It was observed :

> ''7. अभिलेख से स्पष्ट है कि खसरा नं. 38/1 की भूमि/मकान आवेदक रमेश चन्द्र एवं उसके भाई

रामनारायण की शामिलाती संपत्ति है तथा खसरा नं. 38/3 की भूमि/मकान आवेदक रमेश चन्द्र के नाम दर्ज है। पैतृक संपत्ति होने पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अनावेदक को उत्तराधिकार में इस संपत्ति में हिस्सा प्राप्त होगा परंतु आवेदक रमेश चन्द्र के जीवित रहते हुए नहीं। अपने जीवनकाल में संपत्ति पर आवेदक रमेश चन्द्र का ही हक है तथा उसका नाम भी राजस्व अभिलेख में दर्ज है। इस संपत्ति पर शामिलाती खाते में अनावेदक राजेश कुमार का नाम दर्ज नहीं है। अतः उसे आवेदक के जीवित रहते हुए इस संपत्ति पर कोई हक प्राप्त नहीं होने तथा राजस्व अभिलेख में उसका नाम दर्ज नहीं होने से, इसे हक में प्राप्त करने तथा उस पर कोई निर्माण का अधिकार प्राप्त नहीं होता हैं।''

8. आदेश पत्रिका दिनांक 12/03/2014 द्वारा उभयपक्ष को सुनने के उपरांत कलेक्टर द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया था। इस प्रकार स्थगन आदेश एकपक्षीय नहीं था।

9. उपरोक्त कंडिका 6 एवं 7 में की गई विवेचना पर कलेक्टर सिवनी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उनसे अपेक्षा है कि राजस्व अभिलेख की प्रविष्टियों एवं विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विचारण करें साथ ही मध्यप्रदेश मेन्टेनेन्स एण्ड वेलफेयर ऑफ पेरेन्ट्स एण्ड सीनियर सिटीजन्स रुल्स 2009 के नियम 19 के तहत उन्हें वरिष्ठ नागरिकों के जीवन एवं संपत्ति के संरक्षण के संबधं में जो उत्तरदायित्व एवं अधिकार सौंपे गये हैं, उनके पालन में आवेदक के हित का संरक्षण करते हुए आवेदक को उचित राहत प्रदान की जाए। प्रकरण के

अंतिम निराकरण तक आवेदक को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अंतरिम राहत प्रदान करने का औचित्य पाया जाता है। यह आदेश निर्देशात्मक न होकर सलाह की प्रकृति का माना जायेगा। कलेक्टर द्वारा विधि के प्रावधानों के तहत एवं सुनवाई उपरांत गुणदोष पर प्ररकण का समुचित निराकरण किया जाए। उभयपक्ष इस आदेश की प्रति के साथ कलेक्टर सिवनी के समक्ष 15 दिवस की समयावधि में उपस्थित हो।''

The order, i.e. order dated 02.09.2014 was not challenged by the petitioner and was thus allowed to attain finality. The District Magistrate in furtherance to the order dated 02.09.2014 and after affording the opportunity of hearing decided the application preferred by respondent No.4 on 27.05.2015. Since the jurisdictional aspect was already decided by the Commissioner, Jabalpur Division, Jabalpur, Collector considered the matter on merit holding :

''15. प्रकरण में संलग्न समस्त दस्तावेज, एवं माता–पिता ओर वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 21 एवं 22 एवं म.प्र. मेन्टेनेन्स एंड वेलफेयर ऑफ पेरेन्टस् एंड सीनियर सिटीजन्स रुल्स, 2009 अधिसूचना दिनांक 02.07.2009 का परिशीलन किया गया, तथा कमिश्नर जबलपुर द्वारा उनके अभ्यावेदन प्रकरण क्रमांक 335/बी–121/13–14 थे पारित आदेश दिनांक 02.09.2014 की कंडिका 6 एवं 7 पर दिये गये निर्देशों का आकृष्ट किया है। सुश्री प्रीति नाग्रेन्द्र नायब तहसीलदार बंडोल एवं सुलह अधिकारी

सिवनी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन का अवलोकन एवं परिशीलन करने पर पाया जाता है कि राजस्व अभिलेख की प्रविष्टि एवं विधिक स्थिति के परिपेक्ष्य में प्ररकण में म. प्र. मेन्टेनेन्स एण्ड वेलफेयर ऑफ पेरेन्ट्स एण्ड सीनियर सिटीजन्स रुल्स 2009 के नियम 19 के तहत उन्हें वरिष्ठ नागरिकों के जीवन एवं संपत्ति के संरक्षण के संबंध में जो उत्तरदायित्व एवं अधिकार सौंपे गये है। अनावेदक राजेश ताम्रकार को अपने वृद्ध पिता की देख–भाल करना आवश्यक है। अनावेदक द्वारा इन दायित्वों के निर्वहन नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आवेदक श्री रमेश ताम्रकार द्वारा जो संपत्तियां अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई है। तथा अपने स्वाअर्जित धन से संपत्तियों पर उसका स्वामित्व एवं अधिकारिता धारित है। प्रश्नाधीन संपत्ति आवेदक की स्व. स्वार्जित नहीं है। पूर्वजों की भूमि संपत्ति है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अनावेदक का इस संपत्ति का 1/6 भाग बतौर हक प्राप्त है। प्लाट नंबर 38/1 की भूमि मकान आवेदक रमेश चंद्र स्वयं उसके भाई रामनारायण के नाम पर दर्ज है। राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन दिनांक 23.03.2014 में प्लाट नं. 38/1 एवं 38/3 में से 702 वर्गफुट पर आवेदक के पुत्र राजेश कुमार द्वारा मकान निर्माण कराने का उल्लेख किया है। चूंकि उपरोक्त संपत्ति प्लाट नं. 38/1 एवं 38/3 आवेदक रमेश चंद्र के पूर्वजों की है। श्री रमेशचंद्र के पिता वृद्ध अवस्था में अनावेदक उसके हक का अधिकार नहीं रखता है तथा स्वाअर्जित संपत्ति पर भी अनावेदक की अधिकारिता नहीं बनती है। अनावेदक के पिता की अर्जित भूमि से दखल भी नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में कालेज रोड़ मुंगवानी रोड़ भैरोगंज प्लाट नं. 15 X 85 =

1775 वर्गफुट ख.नं. 22/16 रकबा 0.012 हें. अनावेदक राजेश कुमार ताम्रकार को जीवन–यापन करने का अधिकार दिया जाता है। शेष संपत्ति पर आवेदक का स्वामित्व हक रहेगा। प्रकरण में सुलह अधिकारी का जांच प्रतिवेदन में यह प्रतिवेदन किया गया है कि आवेदक रमेश चन्द्र ताम्रकार द्वारा उसके शासकीय सेवाकाल के दौरान दिनांक 24.12.2009 को पंजीकृत बैनामा के आधार पर अनावेदक राजेश कुमार ताम्रकार के नाम से क्रय किया गया है जिसमें वर्तमान में अनावेदक का कब्जा एवं परिवार सहित निवासरत् है। आवेदक द्वारा उठाया गया यह मुद्दा कि अनावेदक राजेश कुमार के नाम से पंजीकृत बैनामा के आधार पर वर्ष 2009 में क्रय किया गया है ऐसी स्थिति में उक्त पंजीकृत बैनामा सम्पत्ति को शून्य किया जाना का मुद्दा इस न्यायालय में विचारणीय होना नहीं पाया जाता है। आवेदक द्वारा उक्त परिसम्पत्तियों को प्रकरण आरंभ होने के पूर्व अनावेदक राजेश ताम्रकार के नाम से पंजीकृत बैनामा के आधार पर स्वयं कर कर पंजीकृत कराया गया है। ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा– 23 के तहत् उठाया गया मुद्दा अपने स्वयं के अंश व स्वत्व का निराकरण करने हेतु सिविल न्यायालय जाने हेतु स्वतंत्र हैं। इसके अतिरिक्त आवेदक के पास वर्तमान में क्रयशुदा सम्पत्तियां जबलपुर/छिन्दवाड़ा जिले में धारित होना पायी जाती है तथा उसकी पैतृक सम्पत्तियां 38/1 एवं 38/3 अतिरिक्त रुप से धारित किया जाना पाया जाता है। चूॅकि आवेदक बैंक से सेवानिवृत्त कर्मचारी होने से उसके जीवन यापन इत्यादि हेतु पर्याप्त सम्पत्तियां भी होना पायी जाती है।''

There being no cogent material being commended at to demolish the findings arrived by the Collector as to entitlement of the petitioner, this Court is not inclined to interfere with the finding of facts.

The next issue is as to whether with the provisions such as Section 5 of 2007 Act it was within the jurisdiction of the Collector to have entertained the complaint. The answer, in the considered opinion of this Court lies in the provisions contained under Section 22 read with Rule 19 of 2009 Rules. That Section 22 of Act of 2007 provides for the Authorities who may be specified for implementing the provisions of the Act of 2007 it stipulates :

> "22. Authorities who may be specified for implementing the provisions of this Act.-
>
> The State Government may, confer such powers and impose such duties on a District Magistrate as may be necessary, to ensure that the provisions of this Act are properly carried out and the District Magistrate may specify the officer, subordinate to him, who shall exercise all or any of the powers, and perform all or any of the duties, so conferred or imposed and the local limits within such powers or duties shall be carried out by the officer as may be prescribed.
>
> (2) The State Government shall prescribe a comprehensive action plan for providing protection of life and property of senior citizens."

Furthermore, Section 32 of 2007 Act empowers the State Government to make rules for carrying out the purposes of the Act of 2007. Clause (e) of sub-Section (2) of Section 32 envisages that without prejudice to the generality of the provisions contained under sub-section (1) of Section 32, the rules may provide for the powers and duties of the Authorities for implementing the provisions of the Act of 2007, under sub-Section (2) of Section 22 of the Act of 2007. The State Government in exercise of the powers conferred under sub-Section (1) of Section 22 has framed the Rules viz. The Madhya Pradesh Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Rules, 2009. Clause (i) of sub-rule (2) of Rule 19 provides for that :

> "19. Duties and powers of the District Magistrate -
> (1) …
> (2) It shall be the duty of the District Magistrate to -
> (i) ensure that life and property of senior citizens of the district are protected and they are able to live with security and dignity;"

Fair reading of these provisions makes it clear that, it is within the jurisdiction of the Collector to entertain an application under Section 22 to ensure that life and property of senior citizens of the District Magistrate are protected and

they are able to live with security and dignity. This view find support from the decision by the Division Bench, High Court of Punjab & Haryana at Chandigarh in Gurpreet Singh vs. State of Punjab CWP No.24508 of 2015 (O & M) decided on 01.12.2015; wherein, it is held by the learned Bench :

> " ... Section 22 falling in Chapter V of the Act enjoins a duty upon State Government to prescribe a comprehensive action plan for providing protection of life and property of senior citizens. Section 32 (2) (f) also empowers the State Government to frame Rules in respect of comprehensive action plan for providing protection of life and property of senior citizens. In terms of such provisions, the Rules have been framed which causes a duty on the District Magistrate to ensure that the life and property of senior citizens are protected and they are able to live with a sense of security and dignity. Apart from framing such Rules, the Action Plan for protection of life and property of the senior citizens has been a licensee, the petitioner is only permitted to enjoy the possession of the property licensed but without creating any interest in the property. A licence stands terminated the moment the licensor conveys a notice of termination of a licence. There is no vested right of any kind in the licensee to remain in possession of the property licensed. Admittedly, respondent No.4 is the owner of the property in question. The petitioner is living in part of the property. Such property

owned by respondent No.4 is required to be protected as mandated by Section 22 of the Act read with Rule 23 of the Rules and para 1 of the Action Plan. There cannot be any effective protection of property of the senior citizen unless the District Magistrate has the power to put the senior citizen into possession of the property and/or to restrain or eject the person who wishes to interfere in the possession of the property of the senior citizen. Protection of the property of a senior citizen includes all incidences, rights and obligations in respect of property in question. Once a senior citizen makes a complaint to District Magistrate against his son to vacate the premises of which the son is a licensee, such summary procedure will ensure for the benefit of the senior citizen. The petitioner would have no right to resist his eviction only on the ground that the Act does not contemplate eviction of an occupant. Eviction is one part of the right to protect the property of a senior citizen which right could be exercised by a senior citizen in terms of provisions of the statute, Rules framed and the Action Plan notified within the jurisdiction of the Act in terms of Section 27 thereof. Since, the protection of life and property fall within the jurisdiction of the District Magistrate, therefore, the District Magistrate is competent authority to take steps for the protection of life and property of the senior citizen.

However, we may say that such summary exercise of the jurisdiction is without prejudice to

> the rights of the parties which may be determined by the Civil Court in accordance with law.
>
> The argument that the order of eviction was ex parte, passed without giving any opportunity of hearing is misconceived. Admittedly, the petitioner was served with a notice. The petitioner has not appeared before the District Magistrate assuming the said day to be non-working day. Once the petitioner was served and has chosen not to appear on the given date and time, the consequences have to be suffered by the petitioner alone. Still further we find that eviction is sought to be resisted on wholly untenable grounds even in the present writ petition."

This Court is in respectful agreement with the view expressed by the learned Division Bench in respect of the scope of Section 22 of 2007 Act.

In the case at hand, since there is uncontroverted finding by the Collector as to the fact that respondent No.4 is wrongly deprived of his right and dignified living, no indulgence is caused.

Consequently, petition fails and is dismissed. Interim order stands vacated. No costs.

(SANJAY YADAV)
JUDGE

anand